P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

प्रगाढ़ होते नेपाल–चीन सम्बन्ध : भारत के लिए उभरती चुनौती

हिन्दुराम
असिस्टेंट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
गायत्री महाविद्यालय,
सांचौर जालोर
राजस्थान, भारत

सारांश

प्रस्तुत शोध–पत्र में बढते नेपाल–चीन सम्बन्ध तथा नेपाल में सत्ता परिर्वतन के बाद वहां की आन्तरिक राजनीति मे चीन के बढते हस्तक्षेप का उल्लेख किया गया है। नेपाल भारत और चीन के मध्य एक ‘बफर स्टेट” के रूप में कार्य करता है तथा यह भारत के उतर पूर्व में स्थित है जो सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण देश है। विगत एक–दो दशक से नेपाल की आन्तरिक राजनीति में बड़ा परिवर्तन हुआ । यहां राजशाही की समाप्ति और माओवादी सरकार अस्तित्व में आई। माओवादी सरकार का चीन के प्रति झुकाव बढा, परिणामस्वरूप भारत नेपाल के सम्बन्धो में दूरी बढी। इस दूरी का फायदा चीन उठा रहा है। चीन नेपाल की भारत पर निर्भरता को घटाने के उदेश्य से वहां पर आधार भूत संरचना का विकास कर रहा है। चीन नेपाल को अपना विश्वसनीय मित्र बनाकर दक्षिण एशिया में अपनी उपस्थिति को सुदृढ कर भारत को घेरने के लिए प्रयत्नशील है । चीन–नेपाल के साथ प्रत्यर्पण सन्धि कर उन तिब्बतियों को नियत्रित करने जा रहा है जो चीन द्वारा तिब्बत में किये जा रहे मानवाधिकारो के हनन एवं तिब्बत में चीन के अवैध कब्जे का विरोध कर रहे है। अतः नेपाल में भारत के लिए बढती चुनौतियो एवं समस्याओ ं के लिए भारत को एक दूरदर्शी एवं स्थायी रणनीतिक नीतिया बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।

मुख्य शब्द : माओवादी, मधेशी आन्दोलन, अवैध व्यापार, पारगमन मार्ग, व्यापार असन्तुलन, स्मॉल स्टेट सिड्रोम, सामरिक हित।

प्रस्तावना

विगत कुछ दशक से नेपाल की राजनीतिक सता में बड़ा परिवर्तन हुआ तथा कुछ घटनाए घटित हुई जिससे दोनो देशो के मध्य सम्बन्धो में गिरावट आई 2008 में नेपाल में राजशाही की समाप्ति तथा संविधान सभा के चुनावों के बाद नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के साथ पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ के नेतृत्व में माओवादी सरकार का गठन हुआ। परिणामस्वरूप माओवादी सरकार का चीन की तरफ झुकाव होने के कारण भारत के साथ सम्बन्धों में कमी आई। नेपाल लम्बे समय भारत–नेपाल शांति–मैत्री सन्धि (1950) की समीक्षा की मांग कर रहा है जिस पर भारत ने अपनी सहमति भी जताई। लेकिन वर्ष 2015 में नेपाल में नए संविधान में मधेशियों के लिए कुछ प्रावधानों को लेकर दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों में कड़वाहट आई। नेपाली प्रधानमंत्री ओली की तरफ से भारत पर आर्थिक नाकेबंदी का आरोप लगाया तथा भारत विरोधी बयान दिए यहाँ तक की सरकार के दबाव में नेपाल के राष्ट्रपति को अपनी भारत यात्रा रद्द करनी पड़ी।

ध्यातव्य है कि भारत ने नेपाल की आंतरिक राजनीति की स्थिरता एवं सीमा पर बसे मधेशियों की राजनीतिक मांगों को देखते हुए सदैव ‘समावेशी संविधान’ बनाने की सलाह दी है। वर्षों की राजनैतिक उथल–पुथल और कई हिंसक संघर्षों के बाद अंततः सितम्बर 2015 में नेपाल में नया संविधान लागू कर दिया गया। इस संविधान का नेपाल के मधेशी, थारू तथा अन्य जनजातीय लोगों ने पुरजोर विरोध किया। मधेशियों ने विरोध–प्रदर्शन के दौरान भारत–नेपाल सीमा को बंद कर दिया जिससे नेपाल में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बंद हो गई थी। मधेशियों के आन्दोलन को लेकर भारत ने असन्तोष व्यक्त किया। मधेशी भारतीय मूल के हैं और वे भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में उनके गहरे संबंध हैं इसलिये इन क्षेत्रों में अशांति का असर भारत पर भी पड़ता। भारत ने उपरोक्त समस्या के प्रति अपनी चिंता से नेपाल को अवगत कराते हुए नए संविधान में कुछ संशोधन का सुझाव दिया गया ताकि विद्रोह शांत हो सके। नेपाल द्वारा

भारत के इस सुझाव को नकार दिया तथा भारत की भर्त्सना करते हुए कहा कि भारत नेपाल के आंतरिक मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे हालांकि दिसम्बर 2015 में नेपाल सरकार द्वारा आन्दोलनरत मधेशियों के आगे झुकते हुए नए संविधान में संशोधन का फैसला लिया था।[1]

भारत –नेपाल (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि)

भारत और नेपाल के बीच अनादि काल से ही पास्परिक संबंध रहे हैं तथा दोनों देशों का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, धर्म, विश्वास, भाषा एवं सांस्कृतिक धरोहर साझी रही है। आजादी के बाद भारत और नेपाल ने अपने संबंधों में मित्रता बनाए रखने हेतु 1950 में शांति और मित्रता की सन्धि की जिससे दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा का संचार किया तथा भारत नेपाल को आर्थिक सहायता प्रदान के लिए प्रतिबद्ध हुआ। जो अभी तक जारी है। भारत ने 1990 के बाद आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई। भारत ने नेपाल के साथ अपने आर्थिक संबंधों को नये आयाम प्रदान किये। नेपाल के विकास के लिये कई कार्यक्रमों को व्यावहारिक रूप प्रदान किये।

नेपाल की भू–अवस्थिति

नेपाल, भारत और चीन के मध्य एक 'बफर स्टेट' के रूप में स्थित है जो चारों ओर से स्थलीय भू–भाग से घिर हुआ है। छोटा देश होने के बावजूद नेपाल दक्षिण एशिया के भू–सामरिक परिवेश में केन्द्रीय स्थिति में है। दक्षिण–पूर्व और पश्चिम में नेपाल भारत के सीमांत से घिरा हुआ है। उत्तर की ओर हिमालय दुर्गम सीमाओं का निर्माण करता है। नेपाल की सीमा 1236 कि. मी. चीन के साथ और 1751 कि.मी. सीमा भारत के पाँच राज्यों से लगती है। यद्यपि भारत–नेपाल के बीच खुली सीमा है। नेपाल की भौगोलिक एवं सामरिक अवस्थिति के कारण इसकी विदेश नीति की वरीयताएँ और विकल्प सीमित हैं। भारत के साथ नेपाल के सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध प्रगाढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच रोटी–बेटी का संबंध है। हिन्दू धर्म के बड़े तीर्थस्थलों में से एक पशुपतिनाथ का मन्दिर और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल में है।2

नेपाल मे चीन का बढता वर्चस्व

नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति के पश्चात् राजनीतिक शक्ति में रिक्तता आ गई थी और चीन इस अवसर का लाभ उठाकर यहाँ भारत के प्रभाव को मंद करने की कोशिश कर रहा है। चीन नेपाल के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में वृद्धि की। इस क्षेत्र में भू–राजनीतिक खेल में चीन ने सदैव भारत के प्रभुत्वशाली प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने की सक्रिय कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि चीन नेपाल के भविष्य की राजनीति निर्धारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

चीन द्वारा तिब्बत के अधिग्रहण के बाद से चीन के लिए नेपाल के सामरिक महत्व में वृद्धि हुई। चीन दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए नेपाल को अपने पक्ष में करना आवश्यक समझता है। चीन की नेपाल नीति मुख्यतया तीन प्रकार से सामरिक हितों से प्रेरित है–

1. – नेपाल में बसे तिब्बतियों की चीन विरोधी नीति पर काबू पाना।
2. नेपाल के साथ भारत के संबंध कमजोर करना।
3. नेपाल में चीन समर्थक राजनीतिक वर्ग तैयार करना।

इसके लिये चीन नेपाल के साथ आर्थिक, राजनैतिक व सैन्य क्षेत्र में लगातार संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा है। चीन नेपाल में अपना निवेश बढ़ा रहा है और द्विपक्षीय व्यापार में भी काफी वृद्धि कर रहा है। चीन द्वारा नेपाल में कई विकासात्मक परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। नेपाल के नए संविधान में भी चीन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे साबित होता है कि चीन के साथ नेपाल की संलग्नता बहुआयामी और दीर्घकालीन होना सुनियोजित है, जिसके तहत चीन नेपाल की भारत पर निर्भरता को कम कर नेपाल को अपनी ओर करना चाहता है। अर्थात् नेपाल के प्रति चीन की यह सक्रिय नीति इस उद्देश्य से प्रेरित है कि दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को कम किया जाए। चीन की नेपाल में रूचि बढ़ने की एक अन्य वजह यह भी है कि चीन ने अपनी घरेलू नीति में बदलाव किया है। अब चीन का ध्यान उसके दक्षिणी भाग की तरफ है। जैसे– तिब्बत, सिजुआन–कुननिंग, झिंजांग, गुयांशू आदि की तरफ है। इन सभी राज्यों की नेपाल से निकटता है इसलिए इन प्रदेशों के आर्थिक विकास, निवेश एवं सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल की बड़ी भूमिका हो सकती है।4

हाल ही के वर्षों में चीन द्वारा भारत की बौद्ध धर्म में प्रमुखता को चुनौती दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था जबकि उनके जीवन की अन्य घटनाएँ भारत से जुड़ी है। अतः विश्व के बौद्ध धर्मावलम्बियों के लिये नेपाल व भारत विशिष्ट आध्यात्मिक स्थल है। भारत के लिये बौद्ध धर्म जहाँ दक्षिण पूर्वी एशियाई व पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों का सांस्कृतिक आधार है जिनके साथ चीन के संबंध अच्छे नहीं है, वहीं दलाई लामा के खिलाफ चीन की साजिशों एवं तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने के कारण चीन हमेशा ही वैश्विक परिदृश्य में अपने लिये प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करता रहा है। इसलिए वह बौद्ध धर्म के भारतीय दावे के समानान्तर स्वयं को बौद्ध धर्म की परम्पराओं से जुड़ा हुआ दिखाने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही वह दलाई लामा के तिब्बती बौद्ध धर्म प्रमुख होने के दावे को भी सिरे से खारिज कर रहा है। चीन जो स्वयं साम्यवादी विचारधारा वाला देश है लेकिन 2006 में आधिकारिक रूप से घोषणा की कि ''बौद्ध धर्म चीन का पुराना शांतिपूर्ण धर्म है।'' और कई बार विश्व बौद्ध मंच का आयोजन कर चुका है जहाँ पर विश्व भर के बौद्ध धर्मावलंबियों को आमंत्रित किया जाता है। नेपाल की चीन के प्रति बढ़ती नजदिकता चीन के इस दावे को ओर मजबूती मिलेगी। चीन नेपाल में स्थिति लुम्बिनी को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। जो भारत के लिए सामरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है।[5]

नेपाल में जल विद्युत की व्यापक सम्भावनाएँ हैं। भारत कई परियोजनाओं में नेपाल के साथ मिलकर काम

भी कर रहा है लेकिन समस्या यह है कि दोनों देशों के मध्य मित्रता की जगह अविश्वास बढ़ रहा है। नेपाल के विद्युत क्षेत्र में भारतीय कम्पनियों को टक्कर देने के लिये चीनी कम्पनियाँ भी इसे क्षेत्र में आ गई। चीन ने नेपाल में चीनी भाषा के कई अध्ययन केन्द्र भी स्थापित किये है जिनका लक्ष्य चीनी सभ्यता, संस्कृति का नेपाल में प्रचार–प्रसार करना है जिनमें अधिकतर केन्द्र भारतीय सीमा के आस–पास के क्षेत्रों में स्थापित किये हैं। चीन के चाइना रेडियो इंटरनेशनल ने काठमांडू में एक एफ.एम. चैनल स्थापित किया है, इनके अलावा चीन द्वारा पोषित एक परस्पर सहयोग समिति का भी निर्माण किया गया जिसका उद्देश्य चीन–नेपाल संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान करना है तथा संस्थागत तरीकों से वह नेपाल को सांस्कृतिक तौर पर जोड़ने का प्रयास भी कर रहा है।[6]

2016 के तत्कालीन प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली अपनी चीन यात्रा के दौरान उन्होंने भारत पर नेपाल की निर्भरता घटाने के उद्देश्य से तिब्बत के रास्ते चीन और नेपाल के मध्य रेल्वे लाइन बिछाने तथा पारगमन व्यापार के समझौते किये। जिसके तहत नेपाल समुद्र के रास्ते अपने व्यापार के लिये चीन के तियानजिन बंदरगाह का उपयोग कर सकेगा। गौरतलब है कि समुद्र के रास्ते व्यापार के लिए नेपाल अब तक भारत के हल्दिया बंदरगाह का उपयोग करता रहा है। चीन और नेपाल के मध्य समझौते के तहत अब चीन नेपाल के पर्यटन स्थल पोखरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएगा। साथ ही नेपाल की पनबिजली परियोजनाओं सहित तेल व उत्खनन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करेगा। चीन नेपाल के सुदूर पश्चिम स्थित हिलसा पुल का निर्माण करेगा। इस पुल के निर्माण के बाद तिब्बत व नेपाल के बीच आवागमन शुरु हो जाएगा। सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि चीन नेपाल के साथ प्रत्यर्पण सन्धि करने जा रहा है जिसके माध्यम से वह नेपाल में बसे उन तिब्बतियों को नियंत्रित कर सकेगा जो चीन द्वारा तिब्बत में किये जा रहे मानवाधिकारों के हनन एवं तिब्बत में चीन के अवैध कब्जे का विरोध करते हैं।[7]

चीन पाकिस्तान के बाद अब नेपाल को अपना विश्वसनीय मित्र बनाने की ओर अग्रसर है। इस प्रकार चीन की दक्षिण एशिया में बढ़ती उपस्थिति जो भारत को घेरने के लिए प्रायोजित है, जो भारत के लिए सामरिक दृष्टि से एक गंभीर चिंता का विषय है। नेपाल स्मॉल स्टेट सिट्रोम से ग्रसित रहा है। चीन नेपाल के मन–मस्तिष्क में यह बात बिठाने में सफल हो चुका है कि भारत बड़ा देश होने की वजह से तथा भौगोलिक कारणों से नेपाल का शोषण कर रहा है।[8]

यह भी उल्लेखनीय है कि जब मधेशी आंदोलन नेपाल में चल रहा था तब उन्होंने ही भारतीय ट्रकों को नेपाल सीमा में नहीं जाने दिया। भारत पर नेपाल को अस्थिर करने का आरोप लगाया। इसी मौके का फायदा उठाकर चीन ने करीब 1000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम तथा अन्य जरूरी वस्तुएँ नेपाल को भेजी। साथ ही, चीन के कई अधिकारी भारतीय सीमा तक आए और सर्वेक्षण किया।

भारत को चीन की 'वन रोड वन बेल्ट' परियोजना से आपत्ति है क्योंकि यह भारत के सामरिक हितों की दृष्टि से प्रतिकूल है जबकि नेपाल ने चीन की इस परियोजना का भाग बनने के लिये अपनी स्वीकृति दे दी है। यह भी स्पष्ट है कि नेपाल के पहाड़ी नेताओं की भारत विरोधी मानसिकता, भारत द्वारा वहाँ चलाई जा रही परियोजनाओं में देरी, नेपाल में भारत की लोकप्रियता में गिरावट आई जिससे नेपाल में भारत की उपस्थिति कमजोर हुई है।

नेपाल–चीन घनिष्ठता : भारत के लिये बढता खतरा

नेपाल की भू–अवस्थिति भारत के लिये महत्वपूर्ण है। भारत के लिये चीन को इस क्षेत्र से दूर रखना अति आवश्यक है। जिस प्रकार लद्दाख क्षेत्र में चीन की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, अरूणाचल प्रदेश को लेकर आक्रामक हो रहा है जिस प्रकार से डोकलाम विवाद गहराया, उस हिसाब से भारत की सुरक्षा के लिहाज से नेपाल, भूटान, म्यामांर को अपनी तरफ करना जरूरी है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से नेपाल बहुत संवेदनशील है क्योंकि भारत के नक्सली और उत्तर–पूर्वी राज्यों के उग्रवादी भी नेपाल की सीमा में अपनी पैठ रखते हैं। भारत में होने वाली अधिकांश आतंकी एवं उग्रवादी घटनाओं के तार सीमा–पार से जुड़े होते हैं। भारत–नेपाल की सीमा खुली हुई है, जबकि नेपाल में माओवादी उग्रवाद का प्रभाव अभी भी बना हुआ है और इस बात के साक्ष्य हैं कि नेपाल के रास्ते चीन ने भारतीय नक्सलियों को धन तथा हथियार मुहैया करवाया है। भारत के लिए परेशानी वाला दूसरा तथ्य यह है कि नेपाल ने काठमांडू, पोखरा से लेकर लुम्बिनी तक सामरिक दृष्टि से कई संवेदनशील क्षेत्र चीन के लिये खोल दिये हैं जहाँ से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड बेहद पास में है।[9]

अतः चीन की ओर नेपाल का बढ़ता झुकाव भारत के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इससे भारत की तिब्बत में पकड़ कमजोर होगी तथा चीन की इस क्षेत्र में उपस्थिति से भूटान के साथ भारत के संबंध भी खराब कर सकता है; अरूणाचल प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर–पूर्वी भारत में उग्रवाद की समस्या को नेपाल के माध्यम से चीन भारत को अस्थिर करने के लिए उग्रवादियों की सहायता कर सकता है। उपरोक्त के अतिरिक्त चीन नेपाल में भारत विरोधी मानसिकता को भी हवा दे रहा है जो भारत के लिए ठीक नहीं है वस्तुतः चीन इस क्षेत्र में नेपाल को 'छोटा चीन' बनाना चाहता है। भारत–नेपाल के बीच खुली सीमा और उपयुक्त कानूनी प्रावधानों की अनुपस्थिति के कारण ड्रग्स और अवैध हथियारों की आवाजाही बढ़ी है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में चीन इस खुली सीमा का दुरुपयोग भारत को परेशान करने के लिए कर सकता है।

ध्यातव्य है कि 30–31 अगस्त, 2018 काठमांडू में सम्पन्न बिम्सटेक सम्मेलन के भारत द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास MILEX–18 (पुणे में) भारत ने बिम्सटेक देशों को आमंत्रित किया था जिस पर सभी सदस्य देशों ने हामी भरी थी लेकिन नेपाल ने अचानक शामिल होने से इन्कार

कर दिया तथा भारत के लिए नेपाल का बड़ा झटका तब लगा जब उसने चीन के साथ 'सागरमाथा फ्रेंडशिप' नामक सैन्य–अभ्यास में शामिल होने के लिए हामी भर दी।

हाल ही में जनवरी, 2019 को नेपाल के केन्द्रीय बैंक ने भारत के 100 रूपए से ज्यादा के 2000, 500 और 200 के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

निष्कर्ष

नेपाल सरकार की अति–महत्वाकांक्षा ही भारत–नेपाल रिश्तों में खटास की वजह बना हुआ है। आवश्यकता है कि दोनों देशों के मध्य पुनः विश्वास की बहाली की जाए जिससे नेपाल में चीन की गतिविधियों को संतुलित किया जा सके। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा 'ओली' अप्रैल, 2018 भारत यात्रा पर रहे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने समानता, आपसी विश्वास सम्मान और लाभ के आधार पर द्विपक्षीय सम्बन्धों को नई ऊँचाईयों तक पहुँचाने के लिए मिलकर काम करने का निश्चय किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मई, 2018 में नेपाल की यात्रा पर रहे। भारत ने नेबरहुड फर्स्ट नीति और भारत–नेपाल के मध्य कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत द्वारा बिहार के रक्सौल से नेपाल के काठमांडू के बीच सामरिक रेल्वे लिंक का निर्माण किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जनकपुर (नेपाल) और अयोध्या के मध्य सीधी बस सेवा का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि उनकी सरकार भारत के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को और मजबूत करने को उच्च प्राथमिकता देती है तथा कहा कि 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल' आदर्श वाक्य के साथ आर्थिक परिवर्तन को प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 'सबका साथ सबका विकास' का भारतीय दृष्टिकोण, समावेशी विकास और समृद्धि के साझा लक्ष्य के लिए अपने पड़ोसियों के साथ भारत के संबद्धता का एक मार्गदर्शक ढांचा है।

सुझाव

इस प्रकार से दोनों देशों के मध्य औपचारिक यात्राएँ हो रही हैं, सम्बन्धों में तीव्रता नहीं है। आज भी नेपाल के लिए चीन उसकी विदेश नीति के केन्द्र बिन्दू में है। भारत को अपनी विदेश नीति में निम्न प्रकार से मंथन की आवश्यकता है–

1. भारत को अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने की जरूरत है। भारत को नेपाल के प्रति नीति दुरदर्शी बनानी होगी जिस तरह से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है।
2. भारत को अपने पड़ोस में आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले रणनीतिक लाभ–हानि पर विचार करना होगा सबसे पहले भारत को दक्षिण एशिया में अपने खिलाफ बने चीन–नेपाल पाकिस्तान गठबंधन का काट ढूंढना होगा।
3. भारत को एक नेतृत्वकर्त्ता की भूमिका निभानी होगी।
4. भारत को गम्भीर और सुलझें प्रयासों के जरिए नेपाल सहित अपने सभी पड़ोसियों को साधने की जरूरत है।[10]

अंत टिप्पणी

1. *विदेश मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट, नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग, विदेश मंत्रालय, मई दिल्ली, 2015–16, पृ. 14–15*
2. *B.M. Jain, India in the New South Asia, Strategic, Military, Ind. Economic concern in the Age of Nuclear Deplomac, New Delhi, Viva Books*
3. *Sikri, Rajiv, Challange and Strategr Relhinking, India's Foreign Policy, New Delhi, Sage Publication, p. 39*
4. *The Hindu News Paper, 23 April, 2016*
5. *फडिया, बी.एल., अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ. 280*
6. *सिंह, निखिल कुमार, हिमालय क्षेत्र का स्वातंत्रिक महत्व, नेपाल एवं भारतीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में, मोहित पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2012, पृ. 159*
7. *अग्रवाल, निर्मला, भारत–नेपाल सम्बन्ध : 1950 की शांति एवं मैत्री सन्धि के सन्दर्भ में अध्ययन, एबीडी पब्लिशर्स, जयपुर, पृ. 58*
8. *राज, एस. विवेक, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इण्डिया, पब्लिशर्स सीविल सर्विसेज टाईम्स, नई दिल्ली, 2012, पृ. 78*
9. *शर्मा, सुमन, इण्डिया एवं दक्षेस, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2001, पृ. 39*
10. *शर्मा, डॉ. रामप्रवेश, भारतीय विदेश नीति तथा हमारे निकटतम पड़ौसी, आर.के. पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, 2009, पृ. 54*